दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 15 ▶ अंक : 3 ▶ गाजियाबाद, मार्च, 2019 ▶ मूल्य : 4 रूपया ▶ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

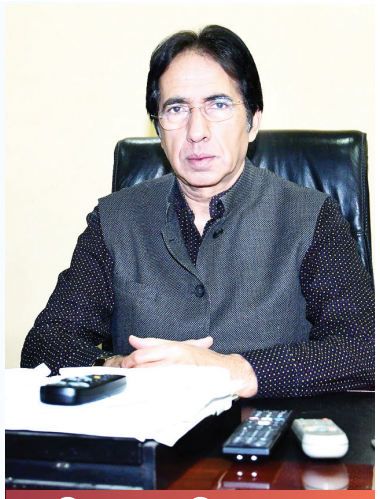

शख्सियत ललित ठुकराल (इ ए सी चेयरमैन).. P-8

करदाताओं को 31 मार्च तक ही कराना होगा आधार–पैन लिंक

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने वालों के लिए आधार–पैन लिंक कराना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया हर हाल में इस साल 31 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए। सीबीडीटी ने गुरुवार को जारी एक निर्देश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगा दी है। **शेष पृष्ठ 3 पर**

क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की हायरिंग कर रहीं सर्वश्रेष्ठ टेक कंपनियां

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। भारत के पेशेवर कार्यबल में हर साल हजारों छात्र जुड़ रहे हैं। ऐसा ट्रेंड भी अब सामने आने लगा है कि टेक्नोलॉजी की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां अब दूसरे शिक्षा के क्षेत्र से पढ़ाई करने वाले छात्रों को अपने यहां नौकरियां दे रही हैं। **शेष पृष्ठ 3 पर**

श्रम विभाग के अधिकारियों को कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए श्रमायुक्त की अनुमति से अब पूरी छूट

उद्योग विहार (मार्च–2019)

गाजियाबाद। श्रम विभाग के अधिकारियों को कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए श्रमायुक्त की अनुमति से अब पूरी छूट प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2019 को जारी आदेश के अनुसार अब अपंजीकृत प्रतिष्ठानों का शत प्रतिशत निरिक्षण होगा जिसके तहत ऐसे प्रतिष्ठान जो दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 या कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं। **शेष पृष्ठ 3 पर**

पाकिस्तान को लगेगा करारा झटका, इन 10 प्रोडक्ट का आयात प्रभावित होगा

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) बढ़ाकर 200 फीसदी कर दिया है। इस कारण पाकिस्तान को झटका लगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से होने वाले आयात पर शुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत किये जाने से ताजे फलों, चमड़ा और सीमेंट सहित 10 प्रमुख उत्पादों के आयात को करारा झटका लगेगा। **शेष पृष्ठ 6 पर**

आपका वंदन है अभिनंदन

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। पाकिस्तान में 60 घंटे बिताने के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने मादरे वतन भारत की सरजमीं पर कदम रखा। अभिनंदन को पाकिस्तान ने अटारी–वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को शुक्रवार रात करीब 9.15 बजे भारत को सौंपा। इस दौरान अभिनंदन के चेहरे पर तेज और गंभीरता थी। गौरतलब है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान 27 फरवरी को सुबह 10 बजे के करीब जम्मू–कश्मीर में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने आए पाकिस्तानी जेट फाइटर्स को अपने मिग–21 बाइसन लड़ाकू विमान से खदेड़ते हुए पाक अधिकृत कश्मीर (च्वज्ञ) में चले गए। उन्होंने एक पाकिस्तानी एफ–16 फाइटर जेट को मार भी गिराया। लेकिन इस दौरान उनका मिग–21 बाइसन भी दुश्मनों के निशाने पर आ गया। अभिनंदन अपने मिग–21 बाइसन से सफलता पूर्व इजेक्ट तो कर गए लेकिन उनका पैराशूट पीओके में लैंड हुआ और उन्हें पाकिस्तान की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया।

इस पूरे घटनाक्रम दस बिंदुओं में...

1. पुलवामा में 14 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन 'जैश–ए–मोहम्मद' के एक फिदायीन आतंकी ने विस्फोटकों से लदी अपनी गाड़ी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बस से टकरा दी। जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए।

2. इस हमले के तुरंत बाद मौलाना अजहर मसूद द्वारा संचालित संगठन 'जैश–ए–मोहम्मद' ने इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी ली। हमले को अंजाम देने वाले फिदायीन आतंकी की पहचान जम्मू–कश्मीर के रहने वाले 20 वर्षीय आदिल अहमद डार के रूप में की गई।

3. पुलवामा हमले के बाद पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि 40 शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उनके खून की एक–एक बूंद का बदला लिया जाएगा।

4. पुलवामा आतंकी हमले के 100 घंटे के भीतर भारतीय सेना ने जम्मू–कश्मीर में मौजूद 'जैश–ए–मोहम्मद' की टॉप लीडरशिप को मौत के घाट उतार दिया। सेना ने कुल तीन जैश लीडर्स को मारा जिसमें पुलवामा आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता गाजी राशिद उर्फ कामरान भी शामिल था।

5. देश अभी 40 जवानों के शहीद होने का गम ही मना रहा था कि जम्मू–कश्मीर के पुलवामा में जैश आतंकियों के खिलाफ इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों के चार और जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के पिंगलिना में सुरक्षाबलों ने देर रात को ऑपरेशन चलाया, जिसका मकसद था गाजी राशिद को पकड़ना। सुरक्षाबल अपने इस मिशन में कामयाब रहे और गाजी को मार गिराया।

6. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग–थलग करने की सफल कोशिश की। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजरायल और यूनाइटेड किंगडम सहित दुनिया के 40 बड़े देशों ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान से उसकी सरजम.ीं पर पल रहे आंतकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा।

7. पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीता.रमण, वित्त मंत्री अरुण जेटली और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल की उपस्थिति में लगातार 'कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी' की कई दौर की बैठकें लीं। जिसके बाद भारत की सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर हाइ अलर्ट घोषित किया गया।

8. केंद्र सरकार ने 24 फरवरी को जम्मू–कश्मीर में 10,000 अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती का फैसला लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक सभा में देश के लोगों से कहा, 'जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है।' उन्होंने देश को लगातार भरोसा दिलाया कि भारत की सुरक्षा में अपनी जान न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।

9. इसके बाद आया 26 फरवरी का वह दिन जिसका सभी भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज–2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के 80 किलोमीटर अंदर घुसकर **शेष पृष्ठ सात पर**

सरकार का 6 करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर्स को तोहफा, ईपीएफ पर ब्याज दर 0.10 प्रतिशत बढ़ाई

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक और तोहफा दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरों में 0.10 प्रतिशत का इजाफा किया है. ईपीएफओ ने एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर को 8.55 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.65 प्रतिशत कर दिया है. ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2016 के बाद पहली बार ब्याज दर बढ़ाई. ईपीएफओ के 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों को इस फैसले का फायदा मिलेगा. आज ईपीएफओ की बैठक में मिनिमम पेंशन पर भी चर्चा की गई लेकिन उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया.

ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक हुई, जिसमें ब्याज दरों में वृद्धि का फैसला लिया गया. श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला ट्रस्टी बोर्ड ईपीएफओ के लिए फैसले लेने वाला शीर्ष निकाय है, जो वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को अंतिम रूप देता है. बोर्ड की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय से सहमति की जरूरत होगी. वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ब्याज दर को अंशधारक के खाते में डाला जाएगा.

ईपीएफओ ने 2017–18 में पीएफ पर 8.55 फीसदी का ब्याज दिया था. ये पिछले 5 साल में सबसे कम था. इससे पहले 2016–17 में 8.65 फीसदी और 2015–16 में 8.8 फीसदी का ब्याज मिला था.

न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर फैसला टला

पीएफ बोर्ड बैठक में न्यूनतम पेंशन पर चर्चा हुई, लेकिन उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया. न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर फैसला आगे के लिए टाल दिया गया है. ईपीएफओ मेंबर्स को अभी 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलती है.

नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर! पीएफ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। देश की सुप्रीम कोर्ट ने पीएफ कैलकुलेशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संस्थान (कंपनियां) बेसिक सैलरी से 'स्पेशल अलाउंस' को अलग नहीं कर सकते हैं. प्रोविडेंट फंड (पीएफ) डिडक्शन के कैलकुलेशन के लिए उन्हें इसे शामिल करना होगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है. इस फैसले से उन कर्मचारियों पर असर नहीं होगा, जिनकी बेसिक सैलरी और स्पेशल अलाउंस हर महीने 15,000 रुपये से ज्यादा हैं.

अब क्या– मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये प्रति महीना है. इसमें 8000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी है और बाकी 7000 रुपये का स्पेशल अलाउंस मिलता है. तो अब आपका पीएफ 8000 रुपये पर नहीं बल्कि 15000 रुपये पर कैलकुलेट होगा. ऐसे में टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, वहीं, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से बढ़ जाएगा. लिहाजा आपका पैसा ज्यादा पीएफ में लगेगा.

क्या है मामला– सुप्रीम कोर्ट की बेंच से पूछा गया था कि क्या संस्थान कर्मचारी को जो स्पेशल अलाउंस देते हैं, वे डिडक्शन के कम्प्यूटेशन के लिए 'बेसिक सैलरी' के दायरे में आएंगे कि नहीं. इस पर फैसला देते हुए जस्टिस सिन्हा ने कहा, तथ्यों के आधार पर वेज स्ट्रक्चर और सैलरी के अन्य हिस्सों को देखा गया है. एक्ट के तहत अथॉरिटी और अपीलीय अथॉरिटी दोनों ने इसकी परख की है. ये दोनों ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अलाउंस बेसिक सैलरी का हिस्सा हैं. इसे छद्म तरीके से अलांउस की तरह दिखाया जाता है ताकि कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में डिडक्शन और कॉन्ट्रिब्यूशन से बचा जा सके. तथ्यों के निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप का मामला नहीं बनता है.

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

श्रम—जगत

02 P.

गाजियाबाद, मार्च, 2019

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING				DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	PUNJAB MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/04/19 TO 30/09/2019	01/02/19 TO 31/07/2019	01/02/19 TO 31/07/2019	10/1/2018	1/1/2018	01/04/2018 TO 30/09/2018	1/1/2018	3/1/2018	01-10-2018 TO 31-03-2019
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-II BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8021.52	9380.31	9834.2	14000	5338.00	7909.20	8497.56	7852.17	4980
SEMISKILLED	8823.67	10300.69	10817.62	15400	5798.00	8117.20	*	8632.17	5445
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	8922.43	*	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	9368.54	*	*
SKILLED	9883.90	11435.41	11801.04	16962	6058.00	8325.20	*	9529.17	5915
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	9836.97	*	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	10328.83	*	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7358.00	10561.17	10845.27	10561.17	*

NEW MINIMUM WAGES IN U.P. ON PAGE 5

30 में केवल एक को नौकरी, अब लगा रहे बेरोजगारी भत्ते का मरहम

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। बेरोजगारी भत्ता देने की नई सरकार की घोषणा के बाद रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने के लिए बेरोजगारों में होड़ मची है। ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए युवा च्वाइस सेंटर का भी रुख कर रहे हैं। आंकड़ें पर गौर करें तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। केवल रायपुर शहर में ही एक लाख से ज्यादा लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। जिला रोजगार कार्यालय में एक लाख पांच हजार लोगों का जीवंत पंजीयन है।

बेरोजगारी दूर करने के लिए प्राइवेट कंपनियों के प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसमें तीन साल में केवल 3213 लोगों को ही काम मिल सका है। यानी औसतन हर 30 बेरोजगार में केवल एक को नौकरी मिली। नई सरकार का बेरोजगारी भत्ता देने का एलान बेरोजगारी के घाव पर मरहम की तरह है। उप संचालक एओ लारी का कहना है कि जीवंत पंजीयन के आकड़े में फिलहाल कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्लेसमेंट के जरिए ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

2015 से अब तक 226 कैंप

जिला रोजगार कार्यालय की ओर से 2015 से अब तक 226 बार प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस बीच प्लेसमेंट कंपनियां कुल 46 हजार रिक्तियां लेकर आईं। इन कैंपों में 37 हजार से ज्यादा युवा पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ 3213 ही लाभान्वित हुए। यानी लगभग साढ़े 11 फीसद को नौकरी मिली। गिनती के लोगों को नौकरी देकर प्लेसमेंट कंपनियों ने वाहवाही लूटी। जिन्हें नौकरी मिली, उनसे प्लेसमेंट चार्ज भी वसूला गया।

2015 में बंद हुआ भत्ता

जीवंत पंजीयन वालों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान 2015 में खत्म कर दिया गया था। नई सरकार का बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश अभी रोजगार कार्यालय में नहीं पहुंचा है। इसका मापदंड क्या होगा, किस कैटेगरी के युवा लाभ ले सकेंगे, कुछ तय नहीं है।

आइटी सेक्टर के लिए उमड़ी भीड़

मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित ऑडिटोरियम में जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से कंप्यूटर डिप्लोमा, साफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके युवाओं को इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी सेक्टर में नौकरी दिलाने के लिए बड़े प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से आयोजित कैंप में सैकड़ों की संख्या में युवा पंजीयन कराने पहुंचे। बड़ी साफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी के इस कैंप में युवाओं ने कैरियर गाइडेंस पर सवाल कर अपनी उलझनें दूर की। योग्यता के आधार पर कंपनी ने रजिस्ट्रेशन और फिर भर्तियां करने का आश्वासन दिया।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD

❖ EVENTS MANAGEMENT
❖ PR MANAGEMENT
❖ ARTISTS MANAGEMENT

http://www.takshakindia.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक सगाचार पत्र

दिल्ली–एनसीआर

03

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, मार्च, 2019

पीएफ विभाग के रिकवरी नोटिस से पूरे दिल्ली एनसीआर में उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में दहशत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर पलीता लगाने पर लगा हुआ है भविष्य निधि विभाग

- अप्रैल 2016 से जून 2017 तक का लाभ कैसे मिलेगा ?
- कर्मचारियों ने जो डाटा दिया उसके आधार पर नियोक्ताओं ने उनका रजिस्ट्रेशन पीएमआरपीवाई पोर्टल पर कर दिया।
- नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की धमकी नोटिस के माध्यम से दे रहे हैं।
- क्या विभाग का सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन के समय ही गलत कर्मचारी को नहीं पकड़ सकता था ?
- क्या विभाग उस वक्त सो रहा था ?
- आम चुनाव के समय उद्योगों एवं व्यापारियों का उत्पीड़न ?

उद्योग विहार (मार्च–2019)

एक ओर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापारियों को एवं श्रमिकों को सुविधाएँ देने के लिए नई नई योजनायें ला रहे हैं वहीं भविष्य निधि विभाग उन योजनाओं पर पलीता लगाने पर लगा हुआ है। अप्रैल 2016 में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक गोल्डन स्कीम पीएमआरपीवाई लाये थे जिसके तहत भविष्य निधि का नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा लेकिन भविष्य निधि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस योजना की ए बी सी डी भी नहीं मालूम थी। उधर जब पी एम ओ से डण्डा चला तथा योजना की प्रगति मांगी गयी तब जुलाई 2017 से विभाग जागा, और उसने अपने कर्मचारियों को एवं नियोक्ताओं को ट्रेनिंग देने का अभियान जोर शोर से चलाया एवं इंस्पेक्टरों को प्रतिष्ठान एवं उद्योगों में भेजा जाने लगा ताकि योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। फिर जब लोगों ने विभाग से पूछा की यह योजना तो अप्रैल 2016 से लागू है फिर अप्रैल 2016 से जून 2017 तक का लाभ कैसे मिलेगा तो विभाग के अधिकारियों ने कहा की उसका पैसा आपके एकाउंट में डायरेक्ट आ जायेगा लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं आया। यह योजना सिर्फ उन नए कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने अप्रैल 2016 में या उसके बाद नौकरी करनी शुरू की है तथा उनका यूएएन नंबर भी अप्रैल 2016 के बाद का है।

जब कम्पनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती की तो कर्मचारियों ने जो डाटा दिया उसके आधार पर यदि वे कर्मचारी अप्रैल 2016 के बाद के थे तो नियोक्ताओं ने उनका रजिस्ट्रेशन पीएमआरपीवाई पोर्टल पर कर दिया। तथा उनका लाभ नियोक्ताओं को मिलने लगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है की नियोक्ता ने तो उन कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कर्मचारियों द्वारा दिए गए डाटा के आधार पर कर दिया क्योंकि उसके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था की वह यह जान सके की इसका पी एफ पहले कटता था या नहीं लेकिन विभाग तो रजिस्ट्रेशन के समय ही पता कर सकता था की जिस कर्मचारी का पीएमआरपीवाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका पहले का स्टेट्स क्या है। जबकि विभाग 2014 से ही पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण का दावा कर रहा है जबकि हकीकत तो नियोक्ता जानता है या श्रमिक, जिसको परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है।

अब विभाग ने उन कम्पनियों को रिकवरी नोटिस भेजना चालू किया है तथा नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की धमकी नोटिस के माध्यम से दे रहे हैं, जिनके यहाँ अप्रैल 2016 से पहले के कर्मचारियों का भी फायदा नियोक्ता को मिल रहा था जबकि नियोक्ता इस बात से अनजान था की वह कर्मचारी अप्रैल 2016 से पहले का है।

सबसे बड़ी एवं सोचने वाली बात यह है की क्या विभाग उस वक्त सो रहा था ? क्या विभाग का सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन के समय ही गलत कर्मचारी को नहीं पकड़ सकता था ? या विभाग ने बिलकुल आम चुनाव के समय उद्योगों एवं व्यापारियों को परेशान करने एवं उनका उत्पीड़न करने का मन बना लिया है। इस सम्बन्ध में ''लॉ ऑफ लेबर'' एडवाइजर्स एसोसिएशन उ प्र के प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने प्रधान मंत्री को पत्र भेज कर माँग की है की इस मामले में तुरन्त उचित कार्यवाही की जाये तथा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का उत्पीड़न ना किया जाये।

पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ा जोरदार अभियान, बिना गोली चलाए किया साइलेंट अटैक

नई दिल्ली। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में भारत ने अपने 40 जवानों को खो दिया था। इस हमले के बाद से पाकिस्तान को विश्व पटल पर अलग–थलग करने के लिए भारत ने एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान छेड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर कई सख्त कदम उठाते हुए आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ने के भी कई इंतजाम किए। भारत के इस साइलेंट अटैक के बाद पाकिस्तान की हालत खराब होना शुरू हो गई है। एक और जहां उसके लिए दुनिया को मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत से सामान आयात बंद होने की वजह से वहां सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं।

भारत के उठाए इन बड़े कदमों से टूटी पाकिस्तान की कमर, हो गई हालत खराब

पिछले साल भारत ने पाकिस्तान से 13724 करोड़ रुपए के सामान का आयात किया था। टैक्स लगने के बाद उस पर बड़ी मार पड़ेगी।

पाकिस्तान पर भारत का साइलेंट अटैक

1– भारत ने वापस लिया एमएफएन (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा

भारत ने पाकिस्तान को 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। जिसके चलते वो अबतक बिना सीमा शुल्क के भारत को सामान निर्यात करता आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

2– अब पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत के हिस्से का पानी

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, अपने हिस्से का पानी पाक नहीं जाने देंगे, कश्मीर और पंजाब में सप्लाई करेंगे। छह नदियों के पानी में से 20 प्रतिशत पानी पर हमारा हक, अबतक हम अपने हिस्से का 95 प्रतिशत इस्तेमाल कर रहे थे, 5 प्रतिशत पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गडकरी के मताबिक, हम पूर्व की नदियों से पानी मोड़कर इसे जम्मू–कश्मीर और पंजाब में सप्लाई करेंगे।

3– पाकिस्तान से आने वाले सामान पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैक्स

4– पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड गाजी मारा गया

सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के चार दिन बाद ही भारतीय सुरक्षाबलों ने इस हमले के मास्टरमाइंड गाजी राशिद उर्फ कामरान को मौत के घाट उतार दिया। हमले के 100 घंटे के भीतर ने सेना ने इस मोस्टवांटेड आतंकी को उसके किए की सजा दे दी। इस मुठभेड़ में गाजी के अलावा जैश–ए–मोहम्मद का एक और आतंकी हिलाल भी मारा गया।

5– हुर्रियत लीडर्स की सुरक्षा वापस ली गई

हमले के बाद जम्मू–कश्मीर प्रशासन ने पाकिस्तान परस्त 18 अलगाववादियों और 155 नेताओं को दी गई सुरक्षा हटा ली। जिनकी सुरक्षा घटाई गई है, उनमें मीरवाइज उमर फारुक, अब्दुल गनी बट, हाशिम कुरैशी, बिलाल लोन, फजल हक कुरैशी, एसएएस गिलानी, आगा सैयद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, यासीन मलिक, सलीम गिलानी जैसे अलगाववादी नेता शामिल हैं।

6– बंद हो गई श्रीनगर–मुजफ्फराबाद बस सेवा

पुलवामा हमले के बाद सरकार ने श्रीनगर और पाकिस्ध्तान के कब्जे वाले कश्ध्मीर के मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली बस सेवा श्कारवां–ए–अमनश को भी रद्द कर दिया। इसके साथ ही जम्मू क्षेत्र के पुंछ और पीओके के रावलाकोट के बीच सीमापार बस सेवा भी रद्द कर दी गई।

7– हाफिज सईद के दो आतंकी संगठनों पर लग गया बैन

पाकिस्तान ने पांच महीने बाद एकबार फिर हाफिज सईद के दो संगठनों जमात–उद–दावा (जेयूडी) और फलाह–ए–इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) पर पाबंदी लगा दी है। पुलवामा हमले के बाद भारत के साथ बढ़े तनाव को घटाने और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक में कार्रवाई से बचने के लिए पाक ने तीसरी बार ये पाबंदी लगाई है।

8– निर्यात बंद करने से व्यापारियों को हो रहा नुकसान, सब्जियों के दाम पहुंचे आसमान पर

– भारतीय किसानों के पाकिस्तान को टमाटर और बाकी सब्जियां निर्यात नहीं करने के फैसले के बाद वहां इन चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। लाहौर में टमाटर की कीमत 180 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।

– पाकिस्तान से आयात पर 200 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय आयातकों ने पाकिस्तान के सीमेंट निर्यातकों से सीमेंट की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही सीमेंट के कंटेनर वापस बुलवाने के लिए कहा है। भारत अबतक पाकिस्तान से सालाना 7 से 8 करोड़ डॉलर (500–572 करोड़ रुपए) की सीमेंट खरीदता रहा है। भारत की ओर से वापस किए गए सीमेंट के कंटेनर फिलहाल कराची, कोलंबो और दुबई पोर्ट पर खड़े हैं।

बता दें कि भारत जहां पाकिस्तान को टमाटर, गोबी, चीनी, चाय, ऑयल केक, पेट्रोलियम ऑयल, कॉटन, टायर, रबड़ समेत 137 वस्ध्तुओं का निर्यात करता है। वहीं पाकिस्तान से वो ड्राइ फ्रूट्स, फल, फ्रेबिक कॉटन, साइक्लिक हाइड्रोकॉर्बन, पेट्रोलियम गैस, पोर्टलैंड सीमेंट, कॉपर वेस्ट और स्क्रैप, कॉटन यॉर्न जैसे 264 प्रमुख उत्पादों का आयात करता है।

पृष्ठ एक का शेष

करदाताओं को 31 मार्च तक ही कराना होगा आधार–पैन लिंक

उद्योग विहार (मार्च–2019)

इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139एए के तहत और सीबीडीटी के 30 जून के आदेश के मुताबिक अब आधार–पैन लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने छह फरवरी को फिर से इसकी पुष्टि की थी कि आइटीआर दाखिल करने वालों को स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ आधार को लिंक कराना ही होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के विरुद्ध केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश फिर से दोहराया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो करदाताओं को आधार और पैन लिंक कराए बिना 2018–19 के लिए आइटीआर दाखिल करने की अनुमति दे दी थी। जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही मामले में फैसला दे दिया है।

क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की हायरिंग कर रहीं सर्वश्रेष्ठ टेक कंपनियां

इसमें लिब्रल आर्ट, डिजाइन एवं डेटा एनेलिटक्स जैसे कोर्स कर रहे छात्रों को नौकरियां मिल रही हैं। इन कंपनियों की इंजीनियरिंग एवं एमबीए कॉलेजों के रूटीन हायरिंग से यह अलग प्रक्रिया है। डिजाइन प्रोफेशनल्स, जिनमें रचनात्मक क्षमता एवं कौशल है उन्हें इंफोसिस, आइबीएम, एसेंचर, कैप जेमिनी, वॉल्ट डिजनी एवं टीसीएस जैसी कंपनियां हायर कर रही हैं। पर्ल अकादमी के छात्रों को 99 फीसद प्लेसमेंट मिली हैं। अकादमी में अगस्त 2018 में हुई प्लेसमेंट सेशन में कुल 733 छात्रों को प्लेसमेंट मिली। कई तरह के क्रिएटिव कोर्स जैसे कम्युनिक. `शन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, फैशन डिजाइन एवं इंटीरियर डिजाइन को करने के बाद छात्रों को सर्वाधिक सैलरी के सालाना पैकेज 8 लाख 50 हजार रूपये ऑफर किए गए।

श्रम विभाग के अधिकारियों को कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए श्रमायुक्त की अनुमति से अब पूरी छूट

उनका श्रमायुक्त की अनुमति से शत प्रतिशत निरिक्षण किया जा सकेगा। उक्त निरीक्षण बिना सूचना दिए आकस्मिक रूप से किया जायेगा। तथा पंजीकृत प्रतिष्ठानों का वार्षिक निरीक्षण किया जायेगा जिसके तहत ऐसे प्रतिष्ठान जो स्व प्रमाणन का चुनाव नहीं करते हैं उनका श्रमायुक्त उ प्र की अनुमति से आवश्यकता अनुसार वार्षिक निरिक्षण किया जा सकेगा। शर्त यह है की निरिक्षण किसी भी दशा में वर्ष में एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा। वहीं शिकायतों के आधार पर निरीक्षण के लिए कहा गया है की किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर श्रम आयुक्त की अनुमति से कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
Editorial
04 P.
गाजियाबाद, मार्च, 2019

सम्पादकीय

देश में अभिनंदन

सत्येन्द्र सिंह

भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की भारत वापसी मौजूदा घटनाक्रम के दौर में एक अहम अध्याय है। पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के जो हालात बने हुए हैं, उनमें पाकिस्तान के कब्जे में फंसे अभिनंदन की स्थिति को लेकर चिंता होना स्वाभाविक ही था। लेकिन इस बीच भारत ने लगातार कूटनीतिक दबाव बनाए रखा और इसी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस करने का फैसला किया। हालांकि यह भी सही है कि इस मसले पर पाकिस्तान ने भारत और यहां के नागरिकों की इच्छाओं का ध्यान रखा और विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को लौटाने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बाकायदा असेंबली में शांति भावना के तहत भारतीय पालयट अभिनंदन की रिहाई का एलान किया। गौरतलब है कि बुधवार को जब पाकिस्तान ने भारत के सीमा क्षेत्र में हवाई बमबारी की थी तब भारतीय वायुसेना के विमानों ने इसका करारा जवाब दिया था। लेकिन इसी क्रम में भारत का एक लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा के इलाके में जा गिरा। इस बीच विमान के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन किसी तरह पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतर तो गए, मगर वहां पाकिस्तान की सेना ने उन्हें कब्जे में ले लिया। इसके बाद भारत के सामने बड़ी चुनौती यही थी कि वह कौन-सा रास्ता अपनाए कि कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके। जाहिर है, भारत ने लंबे समय में दुनिया भर में जो साख बनाई है और ताजा संकट में भी कूटनीतिक स्तर पर जिस तरह की पहलकदमी की, उसकी वजह से कई देशों ने भारत के पक्ष में साफ राय जाहिर की और इससे पाकिस्तान पर दबाव बना। अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कमांडर अभिनंदन को वापस करने के लिए पाकिस्तान ने दबे-ढके शब्दों में शर्त की तरह बातचीत का जो प्रस्ताव रखा था, उससे भी उसे पीछे हटना पड़ा। इस बीच भारत की ओर से लगातार दबाव बनाए रखा गया और इसी का हासिल है कि पाकिस्तान से कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी संभव हो सकी। वरना यह किसी से छिपा नहीं है कि भारत के सैनिकों के प्रति पाकिस्तान का क्या रवैया रहा है। अनेक फौजी आज भी पाकिस्तान की कैद में अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं और उनके मामले में पाकिस्तान ने कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। निश्चित रूप से विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी हमारे देश के लिए एक शानदार उपलब्धि है। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर हालात यहां तक क्यों पहुंचे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के बयालीस जवानों की जान चली गई। उस हमले के पीछे कौन है, अब यह समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने की खबरें अब पुष्ट हो चुकी हैं। भारत की जरूरत और मांग सिर्फ इतनी है कि आतंकी संगठनों को पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे। मगर बार-बार के आश्वासनों के बावजूद पाकिस्तान ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

योगी के बजट से लोगों को तो फायदा होगा पर मोदी को होगा या नहीं... ?

योगी आदित्यनाथ ने बजट में चुनाव को देखते हुए चौके–छक्के की भरमार लगा दी। बजट में उन्होंने मध्यम वर्ग के साथ अपनी संस्कृति और धर्म पर भी जोर दिया। संस्कृत पाठशालाओं पर ध्यान देना जरूरी था नहीं तो आगे चलकर इनका भी वजूद खतरे में पड़ जाता क्योंकि कोई भी सरकार संस्कृत पाठशालाओं और विश्व. विद्यालय की ओर ध्यान नहीं दे रही थी। मदरसों पर भी ध्यान देना जरूरी था क्योंकि धार्मिक तालीम से कुछ नहीं हो सकता, समय के अनुरूप बदलाव की आवश्यकता होती है यदि रोजगार परक शिक्षा चाहिये तो आधुनिक शिक्षा अतिआवश्यक है। योगी सरकार ने बजट में धार्मिक एजेंडे को भी धार दिया साथ ही मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्धता जताई वह बहुत ही सराहनीय कदम है।

प्रदेश के विकास के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है। गांव, गरीब, किसान, महिलायें, व्यापारी और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए सही कदम उठाया गया है। समाज में जिस तरह भ्रूण हत्या हो रही है और बच्चियों की संख्या कम हो रही है उसके लिए कन्या सुमंगला योजना लाना अतिआवश्यक था। यह कदम उठाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सही फैसला किया। इससे बेटियों के पैदा होने से लेकर उनकी पढ़ाई और शादी तक की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत सही है क्योंकि आम आदमी बेटियों की पढ़ाई और शादी में ही परेशान हो जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद शादी के समय दहेज देना ही पड़ता है जिससे आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से प्रदेश में बेटियों की संख्या में अच्छी खासी गिरावट आ रही थी। इस योजना से काफी हद तक गरीबों को सहारा मिलेगा। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के लिए जो मसौदा पेश किया है उससे तो हिन्दुओं का साथ तो मिलेगा साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखा जाये तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक आधार पर मथुरा, काशी, अयोध्या पर्यटन का मुख्य केन्द्र हैं क्योंकि धार्मिक लोग दर्शन–पूजन के लिए काशी में बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन, मथुरा में द्वारकाधीश, वृंदावन में बांके. बिहारी, इस्कॉन मंदिर और अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि, हनुमान गढ़ी मंदिर आदि धार्मिक स्थानों पर आते हैं। इसके साथ ही अन्य छोटे पर्यटन स्थलों का भी ध्यान दिया गया। प्रयागराज स्थित ऋषि भारद्वाज आश्रम एवं श्रृंगवेरपुर धाम, विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य का विकास, बौद्ध परिपथ में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशाम्बी एवं संकिसा का विकास, शाकुम्भरी देवी एवं शुक्रताल का

विकास, राजापुर चित्रकूट में तुलसी पीठ का विकास, बहराइच स्थित महाराजा सुहेलदेव स्थल एवं चित्तौरा झील का विकास तथा लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास भी समय की मांग थी। वहीं देखा जाये तो प्रदेश के विकास के लिए सड़कें अहम रोल अदा करतीं हैं क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो कोई भी निवेशक प्रदेश में नहीं आयेगा। इसलिए प्रदेश को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस–वे का भी निर्माण अतिआवश्यक है इसका भी बजट में ध्यान दिया गया। प्रदेश के विकास में पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस व डिफेंस कॉरिडोर अहम रोल अदा करेंगे। गरीबी की बात करना अलग है और उसमें अमल करना अलग है क्योंकि गरीब किसानों के बारे में सिर्फ कहने से आय दोगुनी नहीं हो जाती साथ ही उनको उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई के साधन, भंडारण और उचित दाम दिलाना अतिआवश्यक है इस बजट में इसका भी ध्यान दिया गया। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में लग रहे 500 हाट–पैठ के निर्माण से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। दुग्ध संघों तथा समितियों को सुदृढ़ बनाने, विस्तार करने तथा कृषकों के प्रशिक्षण के साथ ही तकनीकी पर भी जोर दिया गया इन सब से भी किसानों को बहुत फायदा मिलेगा।

वहीं सूक्ष्म व लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री ने जो प्रतिबद्धता जताई थी उस पर सरकार खरी उतरी, सरकार छोटे एवं मझोले उद्योग को बढ़ाने के लिए एक जनपद–एक उत्पादश (ओडीओपी) लेकर आयी थी। हर जिले की छोटे लघु उद्योगों से अपनी पहचान थी जिसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया था इस बजट में इन सब पर भी ध्यान दिया गया। वहीं प्रदेश के परंपरागत कारीगरों तथा बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची व राजमिस्त्री के उत्थान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की भी शुरूआत की गयी जिसमें मजदूर समेत अन्य गरीब तबकों के लिये तीन हजार रूपये सालाना पेंशन की भी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने बजट में बुंदेलखंड और विंध्य का विशेष ध्यान रखा। इन दोनों क्षेत्रों को विकास से जोड़ा जायेगा। बुंदेलखंड में पाइप लाइन से पेयजल योजना की शुरुआत की जायेगी। वहीं मध्य प्रदेश की सहमति मिली तो केन व बेतवा नदी को जोड़ने का काम भी जल्द ही शुरू हो जायेगा, जिससे बुंदेलखंड के किसानों को राहत मिलेगी। बुंदेलखंड में पानी की समस्या हमेशा से ही रही है। योगी सरकार बुंदेलखंड में सभी सीटें जीती थी यदि अब वहाँ के लिए कुछ नहीं करते तो उनके वोट बैंक पर अच्छा खासा असर पड़ता इस वजह से विषेश ध्यान दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान किया गया 'आयुष्मान भारत योजना' से छूटे गरीबों को लाभ देने के लिए 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान' की शुरुआत की जायेगी। इसके तहत 10 लाख पात्र गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जायेगी, साथ ही कैंसर संस्थान का विस्तार करना और पाँच जिलों के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड भी किया जायेगा। रोबोटिक सर्जरी की भी शुरुआत की जायेगी। गाँवों में चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1000 आयुर्वेदिक अस्पताल बनाये जाने की घोषणा की गई। प्रदेश सरकार जानती है कि सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का है क्योंकि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ठीक नहीं है हर जगह नई तकनीकी की माँग हो रही। इस बजट में चिकित्सा स्वास्थ्य से ज्यादा चिकित्सा शिक्षा पर जोर है क्योंकि प्रदेश में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है।

अब योगी सरकार पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लिए जुटी और नये थाने भी खोलेगी, साथ ही उनके रहने के लिए नए आवासों का भी निर्माण करायेगी। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे घरों में रहने वालों के लिए पक्का मकान देने की भी घोषणा की है जो चुनाव में अहम किरदार अदा करेगी। विरोधियों की बात करें तो 'कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना...' क्योंकि सभी को अच्छाइयां कम बुराइयां ज्यादा दिख रही हैं। किसी को चुनावी बजट लग रहा है तो जो खुद भ्रष्ट हैं उनको यह लगता है कि योगी के पाप कुंभ स्नान से भी नहीं धुलेंगे। खुद की जब सरकार थी तो उन्होंने ऐसे कार्य नहीं किये अब अगर कोई कर रहा है तो उसमें भी नुक्स निक. ालने में लगे हैं। अब देखना यह है कि योगी सरकार के इस लुभावने बजट से लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है, यह तो वक्त ही बतायेगा।

शराब का कहर

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब ने फिर कहर बरपाया है। सहारनपुर, शामली, कुशीनगर, हरिद्वार, रुड़की सहित कई जगहों पर जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। अस्पतालों में इलाज करा रहे पीड़ितों की तादाद तो और भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा मौतें हरिद्वार और इससे सटेउत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुई हैं। यह घटना बताती है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जाहिर है, ये राज्य शराब माफिया की गिरफ्त में हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तो आंखें मूंदे हुए हैं और किसी पर भी कार्रवाई कर पाने में लाचार है। हमेशा से होता यही आया है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फौरी और रस्मी तौर पर कुछ अधिकारी–कर्मचारी निलंबित किए जाते हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देकर पिंड छुड़ा लिया जाता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई किसी पर नहीं होती, जिससे कोई सबक ले सके। वही अब भी हुआ है। जहरीली शराब का कारोबार करने वालों का जाल काफी बड़ा है। जिस तरह यह धंधा चलता आ रहा है उससे तो लगता है कि यह व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। और जहरीली शराब ही क्यों, इस तरह के कई अवैध कारोबार होते हैं जिनके बारे में सरकारें, प्रशासन और पुलिस सब जानते हैं, लेकिन उन पर लगाम नहीं लगाते। यह कोई छिपी बात नहीं है कि अवैध शराब का धंधा स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ही चल पाता है। कच्ची शराब का सेवन आमतौर पर निचले तबके के लोग करते हैं, क्योंकि यह सस्ती होती है और आसानी से मिल जाती है। इसलिए निम्न–वर्गीय बस्तियों, झुग्गी बस्तियों में कच्ची शराब के मटके ज्यादा चलते हैं। पाउचों तक में शराब बिकती है। ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर चलता है। पर पुलिस और प्रशासन इन्हें इसलिए चलने देता है, क्योंकि ये धंधे उगाही के बड़े स्रोत होते हैं। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसे रफा–दफा कर दिया जाता है और थोड़े दिन बाद फिर से धंधा शुरू हो जाता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन कठघरे में आएगा ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से हुई मौतें बता रही हैं कि इन राज्यों की सरकारों ने सत्ता में आने के बाद शराब माफिया पर डंडा चलाने की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि शराब माफिया के सामने हाथ खड़े कर दिए। अगर शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलता तो लोग मारे जाने से बच सकते थे। शराब की बिक्री राज्य सरकारों के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत होती है, लेकिन अवैध शराब का कारोबार करने वालों से जो उगाही होती है, वह भी मामूली नहीं होती। इसलिए चाहे किसी पार्टी की सरकार सत्ता में रहे, शराब माफिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और इसीलिए अवैध शराब के धंधे पर लगाम नहीं लग पाती। यह कोई पहला मौका नहीं है जब जहरीली शराब के कारण इतनी मौतों की खबर आई हो। चार साल पहले लखनऊ के मलिहाबाद में जहरीली शराब से पैंतीस से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि ऐसे बड़े हादसों के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलतीं। पिछली घटनाओं से भी कोई सबक नहीं लिया जाता। अगर सरकार ठान ले तो जहरीली शराब बेचने वालों का सफाया करना कोई मुश्किल काम नहीं है!

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, मार्च, 2019

श्रम विभाग नोएडा ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं तोड़ी

श्रम विभाग का एक पक्षीय आदेश के मामलों में आर सी जारी करने का अधिकार समाप्त

❑ श्रम विभाग नोएडा में भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है, श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा वसूली का एक सूत्री कार्यक्रम किया जा रहा है तथा कहा जा रहा है की श्रम मंत्री को उनका हिस्सा देना है हमने यहाँ पर लाखों रुपए देकर पोस्टिंग करवाई है तो क्या हमें कमाने का अधिकार नहीं है।

उद्योग विहार (मार्च–2019)

श्रम विभाग के अधिकारी फर्जी यूनियन के नेताओं एवं कुछ तथाकथित दलालों के साथ मिलकर कारखानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाते हैं और कारखाना मालिकों का शोषण करते हैं।

अभी हाल ही में एक कारखाना मालिक की कम्पनी के खिलाफ इन लोगों ने इसी तरह साजिश करके पहले उसकी कम्पनी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित किया फिर तहसील से एक करोड़ सत्तर लाख रुपये की आर सी जारी की फिर जब उसने पुनः सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिया तो इन्होने सुनवाई नहीं की तथा अगली तारीख लगाते हुए उसके मालिक को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। तथा सलाखों के पीछे से निकलवाने के एवज में लाखों रुपये की माँग रखी।

इस सम्बन्ध में जब नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठुकराल को जानकारी हुई तो उन्होंने

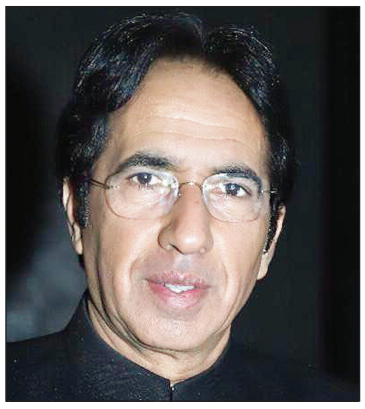

❑ फर्जी श्रमिक यूनियन के साथ मिलकर श्रम विभाग द्वारा एक करोड़ सत्तर लाख रुपये की आरसी जारी करके कारखाना मालिक को सलाखों के पीछे पहुँचाया।

कहा की हम कारखाना मालिक से कुछ पैसे जमा करवा देते हैं लेकिन आप

- ललित ठुकराल इस मामले को निबटाने ले लिए उप श्रमायुक्त को फोन मिलाते रहे लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
- सहायक श्रमायुक्त प्रभाकर मिश्रा का कहना है की वे श्रम मन्त्री के खास आदमी है डी एम उनका क्या बिगाड़ लेगा।
- उप श्रमायुक्त नोएडा से उनके ही विभाग के कर्मचारी नाखुश।
- उप श्रमायुक्त नोएडा का रवैया बहुत ही खराब है तथा वे सिर्फ पैसों की भाषा ही समझते हैं।
- मुख्यमन्त्री से मिलकर पूरे मामले से उनको अवगत करवाया जायेगा तथा इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की माँग की जाएगी।

–पी पी सिंह, महासचिव, नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर

उनको छोड़ दो लेकिन सहायक श्रमायुक्त प्रभाकर मिश्रा ने मना कर दिया तथा कहा की पूरा पैसा जमा करना होगा तभी हम वाद की पुनरीक्षण याचिका को मंजूर करेंगे।

जबकि इस फर्जी मुकदमे में श्रम विभाग के अधिकारीयों ने फर्जी श्रमिक नेताओं के साथ मिलकर ऐसे कर्मचारियों का भी मुकदमा लगाया था जो कभी उनकी कम्पनी में कार्य भी नहीं करते थे तथा उसमे ऐसे कर्मचारी भी शामिल थे जो उनके यहाँ वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और उनका कम्पनी से कोई विवाद नहीं है। तब उन्होंने शासन से बात की तब शासन के हस्तक्षेप से जिलाधिकारी के बीच में पड़ने के बाद उसका पुनः सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा उसे छोड़ा गया।

इस मामले में जिलाधिकारी बी एन सिंह ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हुए मामले का तुरन्त संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी किया की अब किसी भी मामले में यदि एक पक्षीय आदेश किया जाता है तो उस मामले में आर सी नहीं जारी की जायगी तथा उन्होंने अपने यहाँ लम्बित सभी आर सी को वापस कर दिया तथा तहसील से भी सभी आर सी वापस मंगवा ली हैं। इस सम्बन्ध में जब उपश्रमायुक्त पी के सिंह एवं सहायक श्रमायुक्त प्रभाकर मिश्रा से बात करने की कोशिश की गयी तो उन्होंने फोन काट दिया तथा फोन नहीं उठाया।

ऑफिसर सिटी–2 के मालिक सुधन रावत धमकी देकर खरीददारों को कराना चाहते हैं चुप

फ्लैट खरीददार दर दर भटकने को मजबूर

उद्योग विहार (मार्च–2019)

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में स्थित ऑफिसर सिटी –2 के खरीददार इस समय अपने आशियाने के लिए जब भी सुधन रावत के पास जाते हैं तो वे तथा उनके गुण्डे जो उन्होंने पाल रखे हैं खरीददारों को धमकाते हैं की चुप रहो नहीं तो तुमक. ो मार कर फिंकवा देंगे। उन्होंने एक मैनेजर प्रदीप झा को इसी काम के लिए रखा हुआ है जो कुछ गुण्डों के साथ गुण्डागर्दी कर रहा है तथा कहता है की हमारे सुधन रावत की पहुँच ऊपर तक है उनका कोई कुछ नहीं कर पायेगा। सुधन रावत ने भी और बिल्डरों की तरह एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा कर खरीददारों का पैसा हजम कर लिया है। तथा खुले आम कहते घूम रहे हैं की सभी सरकारी अधिकारी बिके हुए हैं सब मेरी जेब में हैं।

सभी खरीददार परेशान हैं तथा किराया के अलावा बैंक का भी लोन एवं ब्याज भर रहे हैं। अब सभी ने मिलकर रेरा में शिकायत करने की योजना बनाई है क्योंकि उनको अब एक यही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। 2014 में सभी को फ्लैट का पजेसन देने की बात कहकर 2011 में फ्लैट बेचे गए थे लेकिन आज तक लोग अपने आशियाने के लिए भटक रहे हैं।

❑ कई लोगों ने तो अपने जीवन की सारी पूँजी लगा दी अब जिन्दगी दाँव पर

जब सुधन रावत से बात की गयी तो उसने कहा की जी डी ए हमें अभी परमिशन नहीं दे रहा है तथा जब इस सम्बन्ध में जी डी ए के अधिकारीयों से बात की गयी तो उन्होंने कहा की हमने कोई रोक नहीं लगाई है। प्रवर्तन जोन–1 के अवर अभियन्ता ने कहा है की जी डी ए द्वारा टावर ब के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। विकासकर्ता का कथन गलत है। इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है की सुधन रावत की कंपनी एम आर प्रोवीयू पूरी तरह से जनता को बेवकूफ बना रही है तथा जनता के पैसे को हड़पने का मन बना कर निश्चिंत बैठी हुई है।

इस सम्बन्ध में जान सुधन रावत से बात की गयी तो उन्होंने कहा की हम दूसरे टावर में फ्लैट दे देंगे उनको उसका जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो देना होगा लेकिन अब खरीददारों का कहना है की हम अब एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाएंगे क्योंकि हमने तो दो बी एच के का फ्लैट लिया था तथा अब वे हमें तीन बी एच के का फ्लैट आज के दाम में दे रहे हैं ये तो सरासर ठगने वाली बात है हम लोग पहले ही कर्जे के बोझ तले दबे हुए है।

पुलवामा हमले में हुये शहीदों को श्रद्धांजलि

उद्योग विहार (मार्च–2019)

गाजियाबाद। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति ने सोमवार 25 फरवरी 2019 को वरिष्ठ नागरिक सभा कक्ष, कविनगर में पुलवामा आतंकी हमले में हुये शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिये एक सभा का आयोजन किया जिसमें जवानों की आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने आतंकवाद की कठोर शब्दों में निन्दा की और कठोर कार्यवाही की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों की शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस अवसर पर समिति की ओर से 1,51000 की धनराशि शहीदों के परिवारों के सहयार्थ देने का फैसला किया गया जो डीएम महोदया के माध्यम से प्रधानमंत्री कोष में दी जाएगी। इस अवसर पर डॉ. रैना, आ.के. गुप्ता, वी.पी.रस्तोगी, विनोद भार्गव, मुकेश खुराबा, हरपाल सिंह आदि व समिति के काफी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे।

उ.प्र. में अब नया न्यूनतम वेतन

उद्योग विहार (मार्च -2019)

उप्र में इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में **1** फरवरी **2019** से नए न्यूनतम वेतन लागू होंगे। जो इस प्रकार है।

50 से ऊपर तथा **500** कर्मचारियों तक

	बेसिक	डीए	नया कुल न्यूनतम वेतन	पिछला न्यूनतम वेतन	कुल बढ़ोत्तरी
अकुशल	7440	1940.31	9380.31	8975.63	404.68
अर्धकुशल	8170	2130.69	10300.69	9856.30	444.39
कुशल	9070	2365.41	11435.41	10942.06	493.35

500 से अधिक कर्मचारियों तक

	बेसिक	डीए	नया कुल न्यूनतम वेतन	पिछला न्यूनतम वेतन	कुल बढ़ोत्तरी
अकुशल	7800	2034.20	9834.20	9409.93	424.27
अर्धकुशल	8580	2237.62	10817.62	10350.93	466.69
कुशल	9360	2441.04	11801.04	11291.92	509.12

साधारण श्रेणी के कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में **1** अप्रैल **2019** से नया न्यूनतम वेतन लागू होगा, जो इस प्रकार है।

	बेसिक	डीए	नया कुल न्यूनतम वेतन	पिछला न्यूनतम वेतन	कुल बढ़ोत्तरी
अकुशल	5750	2271.52	8021.52	7675.45	346.07
अर्धकुशल	6325	2498.67	8823.67	8483.00	380.67
कुशल	7085	2798.90	9883.90	9457.49	426.41

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक सगाचार पत्र

उद्योग–जगत

06 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, मार्च, 2019

पाक पर भारी पड़ेगा एमएफएन दर्जे की वापसी

भारत के दबाव से चरमराई पाक की अर्थव्यवस्था

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति नए सिरे से शुरु की है वह पाकिस्तान के आर्थिक हालात के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। पड़ोसी देश से सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा वापस लेने का फैसला भी दूरगामी असर वाला साबित होगा और इससे निवेशकों को जुटाने के लिए पाकिस्तान पीएम इमरान खान की कोशिशों पर भी पानी फिर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय जगत की प्रतिष्ठित थिंक टैंक ब्रूकिंग्स के फेलो ध्रुव जयशंकर का कहना है कि पूर्व में भी भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को जब अलग–थलग करने की कोशिश की है तो उसका पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर काफी असर पड़ा है।

जयशंकर ने इस बारे में विस्तार से ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को फाइनेंसिएल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के तहत डालने की मुहिम चलाई जिसका

असर यह हुआ है कि उसकी कठोर निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) में उसे डाल दिया गया है। इससे चीन भी नहीं बचा सका। इसके असर से पाकिस्तान को बड़ा झटका लग चुका है। उसकी मुद्रा में भारी अवमूल्यन हो चुका है, उसकी क्रेडिट रेटिंग घटाई जा चुकी है, शेयर बाजार काफी गिर चुका है, विदेशी निवेशक भाग चुके हैं।

वर्ष 2014 के बाद से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद में भारी गिरावट के पीछे भी यही वजह है कि पाकिस्तान की आतंकी भूमिका को लेकर सारे देश सतर्क हुए हैं। हालात यह है कि वर्ष 2014 के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय जहां दोगुनी हो चुकी है वही पाकिस्तान की आय में महज 50 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। भले ही आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रवैये पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन भारत की तरफ से लगातार दबाव का असर उसके आर्थिक हालात पर जरुर दिखाई देता है।

इसके अलावा जब अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा खत्म होगा तो इससे चीन की तरफ से पाकिस्तान में होने वाले निवेश पर भी असर पड़ेगा। निवेश प्रभावित होने की वजह से चीन पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है कि वह अपनी राह बदले। चीन की तरफ से पाकिस्तान से जुड़ी परियोजनाओं में 19 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है जिसका एक बड़ा हिस्सा वहां की ऊर्जा परियोजनाओं में किया जा रहा है। चीन की कंपनियां भारत में भी बड़ा निवेश कर रही है। सिर्फ चीन की टेलीकाम कंपनियां भारत में 7 अरब डॉलर का निवेश कर रही हैं। ऐसे में चीन यह भी नहीं चाहेगा कि भारत में होने वाले निवेश पर भी असर हो।

आर्थिक तूफान की कगार पर दुनिया, आईएमएफ ने सभी देशों को चेताया

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर दुनिया को आगाह किया है. आईएमएफ ने दुनिया भर की सरकारों को सचेत करते हुए आर्थिक विकास उम्मीद से कम रहने पर उठने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है. आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगार्ड ने दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में कहा, 'हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं जो अनुमान से भी कम रफ्तार से वृद्धि कर रही है.' आईएमएफ ने पिछले महीने ही इस साल की वैश्विक आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान 3.7 फीसदी से घटाकर 3.5 फीसदी कर दिया था. लगार्ड ने उन कारकों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने की वजह बताया, जिन्हें वह अर्थव्यवस्था के ऊपर मंडराने वाले 'चार बादल' बताती रही हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि तूफान कभी भी उठ सकता है.

उन्होंने कहा कि इन जोखिमों में व्यापारिक तनाव और शुल्क बढ़ना, राजकोषीय स्थिति में सख्ती, ब्रेक्जिट को लेकर अनिश्चितता और चीन की अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने की रफ्तार तेज होना शामिल है. उन्होंने कहा कि विश्व की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच जारी शुल्क युद्ध का वैश्विक असर दिखने लगा है.

आईएमएफ चीफ ने सरकारों को संरक्षणवाद से बचने की सलाह देते हुए कहा, 'हमें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि यह किस तरह खत्म होने वाला है और क्या यह व्यापार, भरोसा और बाजार पर असर दिखाने की शुरुआत कर चुका है?' लगार्ड ने कर्ज की बढ़ती लागत को भी जोखिम बताया. उन्होंने कहा, 'जब इतने सारे बादल छाये हों तो तूफान शुरू होने के लिए बिजली की एक चमक काफी है'।

सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश देगा रिजर्व बैंक

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि वह अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 28,000 करोड़ रुपये देगा. आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि सीमित आडिट व वर्तमान आर्थिक पूंजी मसौदे की समीक्षा के बाद निदेशक मंडल ने 31 दिसंबर 2018 को समाप्त छमाही के लिये अंतरिम अधिशेष के रूप में केंद्र सरकार को 280 अरब रुपये हस्तांतरित करने का निर्णय किया है. यह लगातार दूसरा साल है जब रिजर्व बैंक अंतरिम अधिशेष हस्तांतरित कर रहा है. इससे पहले, केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले चार साल में सरकार की ओर से की गई विभिन्न सुधारों और नीतिगत उपायों तथा उसके प्रभावों को रेखांकित किया.

सिर्फ छह माह के योगदान पर ले सकेंगे सुपर स्पेशिएलिटी इलाज

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ईएसआइसी की सुविधा उठाने वाले लोगों को बड़ी राहत है। अब वे सिर्फ छह महीने के योगदान पर ही सुपर स्पेशिएलिटी इलाज का लाभ उठा सकेंगे। पहले इसके लिए दो साल तक इंतजार करना पड़ता था। इतना ही नहीं, नियोक्ता और कर्मचारियों की ओर से योगदान को भी घटाकर वेतन का क्रमशः चार फीसद और एक फीसद कर दिया गया है।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अगुवाई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) बोर्ड की बैठक में बीमित व्यक्ति के आश्रितों मसलन पुत्र, पुत्री, माता और पिता के लिए न्यूनतम मासिक आय को भी मौजूदा 5,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये करने का फैसला लिया गया है। बोर्ड ने कहा कि ईएसआइसी राज्यों द्वारा संचालित अस्पतालों के पूरे खर्च का भुगतान करेगा। ये ऐसे अस्पताल हैं, जिनके साथ उसका बीमित व्यक्ति के इलाज के लिए करार होगा। अभी ईएसआइसी 87.5 फीसद खर्च का भुगतान करता है। शेष 12.5 फीसद खर्च संबंधित राज्यों को उठाना पड़ता है। यूनियनों ने सुझाव दिया है कि यदि ईएसआ. इसी द्वारा पूरा खर्च देने के बाद भी भविष्य में इन अस्पतालों की सेवाओं में सुधार नहीं होता है तो उसे इन अस्पतालों को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। बैठक के दौरान बोर्ड को यह भी बताया गया कि ईएसआई योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारियों की ओर से योगदान को भी घटाकर वेतन का क्रमशः चार फीसद और एक फीसद कर दिया गया है।

15 हजार से कम आय पर ले सकते पीएम श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। एएलसी नूतन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है। कोई भी असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगार जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो और किसी भी सरकारी योजना का फायदा न ले रहा हो।

जिला में योजना के तहत 120 कामगारों को पंजीकृत किया जा चुका है तथा 40 कामगारों को कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ से श्रम विभाग के प्रधान सचिव महावीर सिंह की ओर से आयोजित वीसी में मिले निर्देशों की अनुपालना में बताया कि असंगठित क्षेत्रों से जुड़े कामगार, घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने

का काम करने वाले कामगार इसका फायदा उठा सकते हैं। योजना के तहत जुड़ने वाले कामगारों को छोटी राशि हर महीने पेंशन योजना में जमा करनी होगी। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी।

यह उठा सकते हैं योजना का लाभ

असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम हो। श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम से जुड़े लोगों को हर महीने तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान हैं। 18 साल की उम्र से इस योजना को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपये जमा करने होंगे और जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपये जमा करना होगा। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

पाकिस्तान को लगेगा करारा झटका, इन 10 प्रोडक्ट का आयात प्रभावित होगा

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। पाकिस्तान से भारत को मुख्य तौर पर 10 उत्पादों का निर्यात किया जाता है। इनमें ताजे फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पादों, खनिज और चमड़ा उत्पाद प्रमुख हैं। इसके अलावा प्रसंस्कृत खनिज, अकार्बनिक रसायन, कच्चा कपास, सूती कपड़े, शीशा और शीशे का सामान पाकिस्तान से आयात होने वाले सामानों में 95 प्रतिशत तक हिस्सा रखते हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विश्वजीत धर ने कहा, 'पाकिस्तान से मंगाये जाने वाले सामान पर शुल्क में भारी वृद्धि के बाद हम उन्हें व्यापार के मामले में अलग थलग कर देंगे। इस स्तर पर शुल्क बढ़ाने से पाकिस्तान का निर्यात एक तरह से पूरी तरह प्रभावित हो जायेगा।' निर्यातकों के संगठन फियो ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किये। फियो महानिदेशक अजय सहाय ने भी कहा कि इस फैसले से पाकिस्तान के निर्यात को करारा झटका लगेगा। पाकिस्तान से दो मुख्य सामान फल और सीमेंट हैं जिनका आयात होता रहा

है और इन पर 30 से 50 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता रहा है। देश के जिन आयातकों ने आर्डर दिये हैं उनके समक्ष यह मुद्दा आयेगा और उन्हें 200 प्रतिात तक आयात शुल्क देना पड़ सकता है। भारत सरकार ने कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुये आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कारवाई करते हुये पाकिस्तान से होने वाले आयात पर शुल्क को बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान को दिये गये सबसे तरजीही राष्ट्र के दर्जे को वापस ले लिया गया। इस आत्मघाती आतंकी हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गये।

स्टार्टअप को 25 करोड़ तक के निवेश पर एंजेल टैक्स नहीं

उद्योग विहार (मार्च–2019)

दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप पर राहतों की बौछारें कर दी हैं। जहां एक तरफ स्टार्टअप में निवेश पर एंजेल टैक्स का छूट दायरा बढ़ाया गया है, वही दूसरी तरफ स्टार्टअप के नियमों में बदलाव करके उसकी टैक्स छूट की अवधि को 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। सबसे अहम यह है कि स्टार्टअप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। अब जिन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है यानी 100 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं उसको भी स्टार्टअप माना जाएगा।

इन फैसलों के बाद कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने ट्वीट में कहा, किसी भी पात्र स्टार्टअप द्वारा जारी शेयरों अथवा जारी किए जाने वाले शेयरों से सभी निवेशकों से प्राप्त कुल 25 करोड़ रुपये तक की राशि पर छूट होगी। यानी 25 करोड़ रुपये तक पर

एंजेल इनवेस्टमेंट पर छूट रहेगी। गौरतलब है कि सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम काफी अहम है। हाल ही में कई स्टार्टअप ने ऐसी शिकायत की थी कि उन्हें एंजेल इनवेस्टमेंट पर टैक्स नोटिस मिल रहे हैं, इससे उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है।

ऐसे मिलेगी राहत

इसके अलावा, 100 करोड़ रुपए नेटवर्थ या 250 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के पात्र

स्टार्टअप की परिभाषा में बदलाव

स्टार्टअप की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। उन इकाइयों को स्टार्टअप माना जाएगा जो अपने पंजीकरण या स्थापना के बाद 10 साल तक परिचालन कर रही हैं। पहले यह समय–सीमा सात साल थी। श्किसी भी इकाई को स्टार्टअप तभी माना जाएगा यदि उसका कारोबार पंजीकरण से लेकर अब तक किसी भी वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो। मौजूदा समय में यह 25 करोड़ रुपए था।

स्टार्टअप में निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (सात–बी) से छूट दी जाएगी। प्रवासियों, वैकल्पिक निवेश कोष–श्रेणी–1 द्वारा पात्र स्टार्टअप में 25 करोड़ रुपए की सीमा के ऊपर के निवेश को भी इस धारा तहत छूट मिलेगी।

जानकारों की राय

टैक्स एक्सपर्ट सुशील अग्रवाल का कहना है कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। दरअसल स्टार्टअप अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बाहर से पैसा जुटाते हैं। इसके लिए वे पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को अपने शेयर जारी करती हैं।

अधिकांश मामलों में यह शेयर असली कीमत के मुकाबले ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं। शेयरों की इस अतिरिक्त कीमत को इनकम माना जाता है। इस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। इसी इनकम टैक्स को एंजेल टैक्स कहा जाता है। अब एंजेल टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये किया गया है। यानी अगर शेयरों की अतिरिक्त कीमत 25 करोड़ रुपये तक हुई तो उसपर टैक्स नहीं लगेगा। फिनटेक कंपनी पेनियरबाए के फाउंडर एंव सीईओ आनंद कुमार बजाज का कहना है कि इससे अब स्टार्टअप में इनवेस्टमेंट बढ़ेगा।

प्रथम पृष्ठ का शेष

आपका वंदन है अभिनंदन

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट स्थित 'जैश–ए–मोहम्मद' के सबसे बड़े आतंकी कैम्प पर लगभग 1000 किलो बम गिराए। भारतीय वायुसेना के विमानों ने पीओके स्थित मुजफ्फराबाद सेक्टर और चकोटी में भी बमवर्षा की।

10. इसके अगले दिन यानी 27 फरवरी को सुबह 10 बजे के करीब पाकिस्तान की वायुसेना के विमानों ने एलओसी से लगे भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना चाहा। लेकिन भारतीय वायुसेना की मुस्तैदी ने दुश्मन देश के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानी जेट फाइटर्स को खदेड़ते हुए दुश्मन देश के एयरस्पेस में चले गए। उन्होंने पाकिस्तान के एक एफ–16 फाइटर जेट को मार भी गिराया। लेकिन उनका मिग–21 बाइसन फाइटर जेट भी दुश्मन देश का निशाना बना गया। वह इजेक्ट करते हुए पीओके में लैंड हुए। विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान सेना ने गिरफ्तार कर लिया।

चुनावी साल में सरकार सभी के लिए राहत का पिटारा खोल रही है। इसी सिलसिले में उसने पीएफ पर ब्याज दर बढ़ा दी है और घर खरीदने वालों को भी तोहफा देने की तैयारी में है।

पीएफ पर ज्यादा ब्याज देगी सरकार

6 करोड़ लोगों को होगा फायदा

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने साल 2018–19 के लिए ब्याज की दर में 0.10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। अब आपको

2016 के बाद पहली बार बढ़ी दर

8.55 प्रतिशत	8.65 प्रतिशत
पुरानी दर	नई दर

ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। पीएफ खाताधारकों की संख्या करीब 6 करोड़ है। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष में 8.55 प्रतिशत ब्याज दर थी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

डाकघर टाइम डिपाजिट अकाउंट में ब्याज

- 6.9 प्रतिशत एक साल के लिए
- 7 प्रतिशत दो साल के लिए
- 7.2 प्रतिशत तीन साल के लिए
- 7.8 प्रतिशत पांच साल के लिए

कब कितनी रही पीएफ पर ब्याज दर

- 2017–18 में 8.55 प्रतिशत
- 2016–17 में 8.65 प्रतिशत
- 2015–16 में 8.8 प्रतिशत

45 लाख रुपए तक के मकान पर टैक्स छूट!

सरकार घर खरीदने वालों को भी तोहफा दे सकती है। इसके तहत अफोर्डेबल हाउस की परिभाषा बदलने की तैयारी है। अब बड़े शहरों में 45 लाख रूपये तक के मकान को इसके दायरे में लाया जाएगा। रिपोर्ट के मुता. बिक, रियल इस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रविार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। अभी बड़े शहरों में 30 लाख रूपये के घर अफोर्डेबल कैटिगरी में आते हैं। नॉन मेट्रो शहरों में 30 लाख रूपये तक के घर अफोर्डेबल हाउसिंग कैटिगरी में आएंगे। अभी नॉन मेट्रो शहरों में 25 लाख रूपये तक के घर अफोर्डेबल इस कैटिगरी में ओ है। जीओएम का अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी 8 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने का सुझाव है। बता दें कि घटे हुए जीएसटी का फायदा पुराने, बिक चुके अफोर्डेबल घर खरीदारों को भी मिलेगा।

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इस 'तीसरी आंख' से बच नहीं पायेंगे पाकिस्तानी घुसपैठिये

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। भारत लगातार अपनी सीमाओं को अभेद्य करने में जुटा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक आला अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरहदों से सटे कुल 2,000 किलोमीटर लम्बे संवेदनशील क्षेत्र की अत्याधुनिक तकनीकों से निगहबानी की जारी महत्वाकांक्षी परियोजना के अगले छह–सात सालों में पूरे होने का अनुमान है। बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक ए के शर्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) पर लगातार काम जारी है। इसके तहत सरहदों की निगहबानी के लिये विश्व की सबसे अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा

रहा है। उन्होंने बताया कि सीआईबीएमएस के तहत अत्याधुनिक उपकरणों को जम्मू स्थित भारत–पाक सीमा के भाग और कुछ अन्य सरहदी क्षेत्रों में लगाने का काम पूरा हो गया है। देश के पूर्वी हिस्से में स्थित भारत–बांग्लादेश सीमा के क्षेत्रों में सीआईबीएमएस से जुड़े काम जारी हैं। उन्होंने बताया कि सीआईबीएमएस से उन संवेदनशील सरहदी क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा गया है, जहां नदियों, पहाड़ों, गड्ढों, खाइयों जैसे अलग–अलग भू–तलों के कारण हर जगह पारंपरिक बाड़ नहीं लगायी जा सकती। उन्होंने कहा, 'सीआईबीएमएस की परियोजना पूरी होने में छह से सात साल का समय लग सकता है। इसके तहत बेहद पुख्ता तकनीकी तंत्र तैयार किया जा रहा है। जैसे ही कोई घुसपैठिया हमारे देश की सीमाओं में दाखिल होने की कोशिश करेगा, तो उसकी यह हरकत इस तंत्र की पकड़ में आ जायेगी।' शर्मा ने बताया कि शुरुआती तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरहदों से सटे कुल 2,000 किलोमीटर लम्बे संवेदनशील क्षेत्र में सीआईबीएमएस की परियोजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है।

आईएलएफएस संकट गहराने से लाखों के पीएफ पर खतरा

उद्योग विहार (मार्च–2019)

नई दिल्ली। आईएलएफएस का कर्ज संकट गहराने से करीब 15 लाख कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (पीएफ) में जमा रकम पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ और पेंशन फंड खाते का ज्यादातर पैसा आईएलएफएस समूह की सहायक कंपनियों में निवेश किया है।

समूह की कई कंपनियों के दिवा. लिया होने पर निवेश की गई रकम डूबने का खतरा मंडराने लगा है। ईपीएफओ ने इस संबंध में राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर कराई है। याचिका में कहा गया है कि उसे अपने पैसे खोने का डर है क्योंकि जिन बॉन्ड के तहत यह निवेश किया था वह असुरक्षित कर्ज के तहत आते हैं। ईपीएफओ ने एनसीएलटी में आवेदन किया है कि आईएलएफएस समाधान प्रक्रिया में उसके निवेश को लौटाने पर तवज्जो दिया जाए क्योंकि 75 कंपनियों द्वारा दायर ऋण वसूली याचिका में उसका नंबर सबसे नीचे है। ईपीएफओ के मुताबिक, उसने जो निवेश किया है वह सुरक्षित कर्ज के तौर पर है जबकि समाधान प्रक्रिया में पहले सुरक्षित कर्जदारों का वकाया चुकाया जाएगा।

कंपनी पर 94 हजार करोड़ बकाया

आईएलएफएस का ऋण संकट पिछले साल जुलाई में सामने आया था, जब वह समय पर कर्ज चुकाने में असफल रही थी। कंपनी पर करीब 94 हजार करोड़ रूपये का बकाया है। कंपनी के शीर्ष स्तर पर अनियमितताओं की भनक लगने के बाद सरकार ने तत्कालीन बोर्ड को बर्खास्त कर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। कंपनियां अपनी परिसंपत्ति बेचकर बकाया चुकाने का प्रयास कर रही है।

उद्योग विहार

निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

शख्सियत

गाजियाबाद, मार्च, 2019

नोएडा में अपैरल पार्क बनने के बाद कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जिसमे से 70 प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

ललित ठुकराल 'इ ए सी चेयरमैन'

परिचयः ललित ठुकराल 'इ ए सी चेयरमैन'

ललित ठुकराल 'इ ए सी चेयरमैन' अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउन्सिल, रेडीमेड गारमेंट्स के संयोजक – यू पी एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल, बोर्ड ऑफ गवर्नर – अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेण्टर, अध्यक्ष– नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर, डायरेक्टर – ट्वेन्टी सेकण्ड माइल्स।

ललित ठुकराल दिल्ली के ही रहने वाले हैं इनका जन्म सन् 1957 में हुआ था। इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा एक बेटी एवं एक बेटा है। बेटी की शादी हो चुकी है तथा बेटे निखिल ठुकराल अपने पिता के साथ ही कम्पनी सँभालते हैं। निखिल ठुकराल देश के प्रतिष्ठित संस्थान निफ्ट से फैशन डिजाइनर हैं।

ललित ठुकराल अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउन्सिल के इ ए सी चेयरमैन हैं, यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल के रेडीमेड गारमेंट्स के संयोजक है तथा अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेण्टर के बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं तथा नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के अध्यक्ष हैं। उनके इतने सारे महत्वपूर्ण पदों से उनकी काबलियत का अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

- सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग श्रम विभाग है जहाँ के अधिकारी व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के साथ सिर्फ शोषण करते हैं।
- पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी थोड़ा है, थोड़े की और जरुरत है।
- श्रम विभाग के अधिकारी फर्जी यूनियन के नेताओं एवं कुछ तथाकथित दलालों के साथ मिलकर कारखानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाते हैं और कारखाना मालिकों का शोषण करते हैं।
- जिलाधिकारी बी एन सिंह का मै बहुत आभारी हूँ।
- अब किसी भी मामले में यदि एक पक्षीय आदेश किया जाता है तो उस मामले में आर सी नहीं जारी की जायेगी।
- ऐसे अधिकारीयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।
- नोएडा का ट्रैफिक सिस्टम बहुत खराब है।

नोएडा को "सिटी ऑफ अपैरल" का दर्जा दिलवाने में ललित ठुकराल का महत्वपूर्ण योगदान है।

ललित ठुकराल ट्वेन्टी सेकण्ड माइल्स के डायरेक्टर है। जो की महिलाओं के आधुनिक फैशन के कपड़ों एवं एक्सेसरीज को बनाती है तथा उनका निर्यात करती है।

उनसे उद्योग विहार के मुख्य संपादक सत्येन्द्र सिंह के साथ बातचीत के प्रमुख अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं।

ललित जी आप इतने अधिक महत्वपूर्ण पदों पर हैं कैसे आप इसके लिए समय निकाल पाते हैं? जबकि आपको अपना बिजनेस भी देखना होता है।

ये लोगों का प्यार है जिन्होंने हमें इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया है। मेरी पूरी कोशिश रहती है की मैं सभी पदों की जिम्मेवारी को निभा पाऊँ तथा उस पर खरा उतर सकूं। मेरे बेटे निखिल ने मेरा बिजनेस संभाल लिया है जिसकी वजह से मैं सभी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा पा रहा हूँ।

बिजनेस में आपको सर्वप्रथम किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या सरकारी विभागों का सहयोग मिलता है?

हमें सबसे अधिक सरकारी विभागों में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसमे से सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग श्रम विभाग है जहाँ के अधिकारी व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के साथ सिर्फ शोषण करते हैं। तथा अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका उत्पीड़न करते हैं। बाकी सभी विभागों में हालाँकि पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी थोड़ा है, थोड़े की और जरुरत है।

श्रम विभाग से आप काफी खफा दिख रहे हैं ऐसा क्या परेशान करते है वे लोग? क्या उनके शासन में बैठे अधिकारी भी नहीं सुनते हैं?

श्रम विभाग के अधिकारी फर्जी यूनियन के नेताओं एवं कुछ तथाकथित दलालों के साथ मिलकर कारखानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाते हैं और कारखाना मालिकों का शोषण करते हैं। अभी हाल ही में हमारे एक सदस्य की कम्पनी के खिलाफ इन लोगों ने इसी तरह साजिश करके पहले उसकी कम्पनी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित किया फिर तहसील से एक करोड़ सत्तर लाख रुपये की आर सी जारी की फिर जब उसने पुनः सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिया तो इन्होने सुनवाई नहीं की तथा उसके मालिक को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। इस सम्बन्ध में जब शासन से बात की गयी तब शासन के हस्तक्षेप से जिलाधिकारी के बीच में पड़ने के बाद उसका पुनः सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा उसे छोड़ा गया।

इस मामले में जिलाधिकारी बी एन सिंह का मै बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मामले का तुरन्त संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी किया की अब किसी भी मामले में यदि एक पक्षीय आदेश किया जाता है तो उस मामले में आर सी नहीं जारी की जायगी तथा उन्होंने अपने यहाँ लम्बित सभी आर सी को वापस कर दिया तथा तहसील से भी सभी आर सी वापस मंगवा ली हैं।

इस समस्या के सम्बन्ध में आपका क्या सुझाव है जो की आप शासन तक पहुँचाना चाहते हैं?

इस सम्बन्ध में मुझे सिर्फ यही कहना है की ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए तथा अवैध यूनियन एवं अवैध लोगों के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि व्यापारियों का शोषण रुक सके। जब तक अधिकारीयों, अवैध यूनियन के नेताओं का गठजोड़ नहीं टूटेगा तब तक श्रम विभाग में शोषण होता रहेगा। मैं अब जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर उनको पूरे तथ्यों की जानकारी दूँगा और हमें पूरी उम्मीद है की मुख्यमंत्री जरूर कड़ी कार्यवाही करेंगे।

इसके अलावा और किन विभागों में आप सुधार की जरूरत समझते हैं ?

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भविष्य निधि, अग्निशमन विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण विभाग में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है काफी कार्य ऑनलाइन होने से व्यापारियों को काफी सहूलियत हो गयी है लेकिन अभी भी पूरी तरह से पेपर लेस करने के लिए काफी कुछ करने की जरुरत है। हालाँकि सरकार इस दिशा में प्रयासरत है बस उसे सही दिशा देने की जरुरत है ताकि व्यापारियों के साथ–साथ श्रमिकों को भी इसका लाभ मिल सके।

नोएडा को "सिटी ऑफ अपैरल" का दर्जा दिलवाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है आप इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ?

हमने इन्वेस्टर सम्मिट में मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सी इ ओ अरुण वीर सिंह के द्वारा ओ डी ओ पी के तहत एम ओ यू पर हस्ताक्षर करवाए। इसमें यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सी इ ओ अरुण वीर सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है।

नोएडा को "सिटी ऑफ अपैरल" का दर्जा क्यों मिला है जबकि यहाँ तो और भी बहुत इंडस्ट्रीज हैं? जैसे आई टी कम्पनियाँ भी बहुत हैं?

नोएडा में आई टी कम्पनियों में एक लाख से भी कम कर्मचारी कार्य करते है जबकि अकेले रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज में लगभग 10 लाख कर्मचारी सीधे सीधे कार्य करते है जबकि लाखों लोग इनसे जुड़े कुटीर उद्योगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। नोएडा से 18 हजार करोड़ का निर्यात हर महिने रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग से ही होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक विशाल 'एपैरल पार्क' को सरकार ने यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बनाने की मंजूरी दे दी है।

यह "अपैरल पार्क" कितना बड़ा होगा, तथा इस "अपैरल पार्क" के आने से क्या क्या फायदे होंगे तथा रोजगार के बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं?

यह अपैरल पार्क 280 एकड़ में विक. सित किया जा रहा है तथा इसके आने से आसपास के एरिया में, जेवर में बहार आ जाएगी तथा आसपास के लोगों को रोजगार मिलेंगे। इस पार्क की वजह से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 70 प्रतिशत रोजगार तो सिर्फ महिलाओं को ही मिलेगा क्योंकि इस इंडस्ट्री में महिलाओं की संख्या अधिक है।

वर्तमान में "अपैरल पार्क" की क्या स्थिति है?

ओ डी ओ पी के तहत शासन ने 250 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। इस प्रोजेक्ट की डी पी आर जमा कर दी गयी है तथा हमने मुख्यमंत्री से इस प्रोजेक्ट के लिए 4000 करोड़ की माँग रखी है। यह प्रोजेक्ट बहुत ही सफल प्रोजेक्ट होगा।

अभी हाल ही में एक श्रमिक यूनियन हिन्द मजदूर सभा जब नोएडा में हड़ताल करने जा रही थी तब उसे खत्म करवाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं ?

हाँ, हमने उस हड़ताल को रुकवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी क्योंकि हमें मालूम है की एक दिन की हड़ताल से व्यापारियों का तो नुकसान होता ही है साथ में श्रमिक भाइयों का भी बहुत नुकसान होता है खासतौर पर दिहाड़ी श्रमिकों का। साथ ही सरकार को भी करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि उठानी पड़ती, इसलिए हमने प्रशासन एवं यूनियन के बीच मध्यस्थता करते हुए इस हड़ताल को रुकवाया था ताकि शहर में अमन एवं शान्ति बनी रहे तथा शहर का माहौल खराब न हो। कारखाने चलने चाहिए तभी रोजगार मिलेगा। तभी लोगों के घरों में चूल्हे जलेंगे।

नोएडा में उद्योगों के लिए क्या सुविधायें जरूरी हैं जो की वर्तमान में सबसे अधिक जरूरी हैं?

नोएडा का ट्रैफिक सिस्टम बहुत खराब है हर गली, हर सड़क पर सुबह ड्यूटी जाते समय या शाम को ड्यूटी से वापस आते समय जाम की समस्या विकराल हो गयी है जिसे अविलम्ब दूर करना चाहिए ताकि लोगों के समय की बचत हो और लोग समय पर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच सकें।

क्या शासन से आपको सहयोग मिलता है?

हमें शासन एवं प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। महेश शर्मा जो की यहाँ से सांसद हैं उद्योगों का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे इस बार फिर यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे।

मै. लीगल इन्फोसोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक "सत्येन्द्र सिंह" द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901 / 4108794 मोबाइल नं. : 9818036460 / 9818697406 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com संस्थापक : शीतला प्रसाद सिंह प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह सम्पादक : बबिता सिंह सह सम्पादक : राजेश सिंह